

रूपए की लुढ़कती कीमत ने भारत-अमेरिका “ट्रेड” समझौते को और जटिल बनाया

अमेरिका को एक और तर्क मिल गया, “टैरिफ” नहीं घटाने के लिए, या कितना टैरिफ घटाना है, उसकी सौदेबाजी के लिए

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। पिछले एक हफ्ते में भारतीय रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुँचने, यू.एस. डॉलर के मुकाबले 90 के पार जाने और एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के तौर पर अपनी जगह पक्की करने से आर्थिक नतीजों की एक लहर शुरू हो गई है, जिसे भारत को सावधानी से मैनैज करना होगा। यह स्थिति ऐसे समय बनी है, जब भारत अमेरिका के साथ एक लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, और रुपये की अस्थिरता अर्थव्यवस्था की गहरी कमजोरियों को उजागर कर रही है।

मुद्रा का यह झटका वॉशिंगटन के साथ भारत की व्यापार वार्ताओं में एक नया पहलू जोड़ता है। कमजोर रुपया भारत को थोड़े समय के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, लेकिन यह जांच को भी बुलावा देता है। अमेरिकी

- तर्क यह है कि रूपए का मूल्य घटने से भारत को निर्यात में माल सस्ता होने का “एडवांटेज” मिलेगा।
- पर, रूपए का मूल्य घटने से, भारत का “ऑयल इंपोर्ट” बिल, जो डॉलर में ही होता है, और बढ़ता जाएगा। “ट्रांसपोर्टेशन” महंगा होने से देश में हर वस्तु के दाम प्रभावित होंगे। साग-सब्जी से कंस्ट्रक्शन मटीरियल तक सब कुछ महंगा होगा तथा हर व्यक्ति का घर खर्च बढ़ेगा।
- विदेश में बच्चों को पढ़ाना, इलाज कराना, विदेशी दवाइयां व उपकरण महंगे हो जाएंगे।
- भारतीय उद्योगपतियों व व्यापारियों में इन दिनों होड़ लगी थी, विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए। यह ऋण और इस ऋण की अदायगी महंगी हो जाएगी।

वार्ताकार तर्क दे सकते हैं कि एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव भारत को पहले ही फायदा दे रहा है, और इससे टैरिफ में कमी पर बातचीत और कठिन हो सकती है।

इस स्थिति की जड़ में है, भारत

के हिसाब से काफी महंगा हो गया है, जिससे तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है और सरकार को ईंधन की कीमतों पर कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं। महंगा ईंधन अर्थव्यवस्था पर तेजी से असर डालता है, माल ढुलाई बढ़ती है और सब चीजें, सब्जियाँ और निर्माण सामग्री से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक, और महंगी हो जाती हैं। यह आयातित महंगाई सीधे घरों के खर्चों पर चोट करती है, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के बजट पर।

विदेश में पढ़ाई, विदेश यात्राएँ, चिकित्सा प्रक्रियाएँ और यहाँ तक कि, आयातित दवाएँ और उपकरण भी काफी महंगे हो गए हैं। जिन परिवारों के बच्चे अमेरिका या यूरोप में पढ़ रहे हैं, उनके मासिक खर्च बढ़ गए हैं क्योंकि टयूशन, रहने और रोजमर्रा का खर्च अब महंगे डॉलर में देना पड़ रहा है। रुपये की गिरावट ने कंपनियों को बैलेंस शीट भी मुश्किल में डाल दी है। जिन कंपनियों पर डॉलर में कर्ज है, उनके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और स्पीकर शिवराज पाटिल का निधन

लातूर/नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज विश्वनाथ पाटिल का शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पाटिल पिछले कुछ समय से उग्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई राज्यों के

- राष्ट्रपति मुर्मू, प्र.मंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों व नेताओं ने शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्रियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने दुःख प्रकट किया है। पाटिल ने लंबे समय तक कई संवैधानिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और पंजाब के राज्यपाल सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया था। पाटिल को एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ और संवैधानिक मामलों के जानकार के रूप में जाना जाता था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने बिहार जीत की खुशी में एनडीए सांसदों को लाजवाब भोज दिया

रात्रिभोज में भारत के विभिन्न प्रांतों के लजीज़ शाकाहारी व्यंजन परोसे गए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 दिसंबर को नई दिल्ली में अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के सांसदों के लिए एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया। यह भोज बिहार विधानसभा चुनावों में हाल ही में मिली विशाल सफलता के बाद आयोजित किया गया था।

केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एनडीए सांसद प्रधानमंत्री के आवास पर जाने के लिए बस में सवार हो रहे हैं। रिजिजू ने लिखा कि “हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आभारी हैं, जिन्होंने एनडीए सांसदों के

- केन्द्रीय मंत्री ने 11 दिसंबर की रात दिए गए रात्रिभोज का वीडियो एक्स पर शेयर किया और रात्रिभोज के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।
- एनडीए के सभी सांसदों को बस में बिठाकर प्रधानमंत्री आवास, 7, लोक कल्याण मार्ग ले जाया गया था।

लिए 7 लोक कल्याण मार्ग पर रात्रिभोज का आयोजन किया। पूरे कार्यक्रम का माहौल बेहद पारिवारिक था।”

मेहमानों का स्वागत ताजगी से भरपूर अदरक वाले संतरे के रस और अनार के रस से किया गया। यह पेय पदार्थ एक शक्तिशाली इम्युनिटी बूस्टर माना जाता है। अदरक का तीखा स्वाद स्वाभाविक रूप से खट्टे मीठे संतरे और मीठे अनार के स्वाद के साथ अद्भुत स्वाद पेश कर रहा था।

खेड़ा को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। कांग्रेस प्रवक्ता और पार्टी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा को सोशल मीडिया एक्स पर उनकी एक पोस्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा गया है। खेड़ा ने यह पोस्ट शुक्रवार सुबह किया था।

यह कानूनी नोटिस “द स्टेट्समैन लिमिटेड” के चेयरमैन और समाचार

- कांग्रेस प्रवक्ता को यह कानूनी नोटिस उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर स्टेट्समैन लिमिटेड के चेयरमैन व यूपएआई के निदेशक आर.पी. गुप्ता ने भेजा है।

एजेंसी यूपएआई के निदेशक आर पी गुप्ता की ओर से भेजा गया है। खेड़ा ने अपने विवादस्पद पोस्ट में यह संकेत दिया है कि देश के “सबसे ऊंचे पद” पर बैठे किसी व्यक्ति ने गुप्ता को एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वायु प्रदूषण नैशनल इमरजेंसी है संसद में इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए’

राहुल गांधी के इस आग्रह पर केन्द्र सरकार ने सकारात्मक रूख दर्शाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक सहयोगात्मक भावना को दर्शाते हुए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद से अपील की कि वह आरोप-प्रत्यारोप से परे जाकर, भारत के बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करे और संकीर्ण दलगत राजनीति से ऊपर उठे।

गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और सरकार के बीच हालिया विवादों के कारण लोकसभा के अंदर और बाहर काफी राजनीतिक तनाव बना हुआ है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह पहल तथा सरकार की वैसी ही प्रतिक्रिया का अवसर पिछले 10 वर्षों में एक दुर्लभ क्षण था, जब दोनों पक्षों ने साझा उद्देश्य की भावना दिखाई।

लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि भारत के अधिकांश बड़े शहर

- दस साल में पहली बार ऐसा दुर्लभ क्षण आया है संसद में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी मुद्दे पर पूर्ण सहमति देखी गई।
- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा भारत के अधिकांश शहरों में हवा ज़हरीली है, बच्चों व बुजुर्गों का स्वास्थ्य इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, इससे निपटने के लिए हमें लोकसभा में चर्चा करनी चाहिए।
- उन्होंने कहा, ना तो यह पुष्टि कि अब तक क्या किया और क्या नहीं किया, ना ही हम आप पर आरोप लगाएं और आप हम पर, बस यह बात की जाए कि देश की भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
- राहुल के प्रस्ताव पर सरकार ने सकारात्मक रूख दर्शाया और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार पहले दिन से ही प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

“जहरीली हवा की चादर के नीचे जी रहे हैं”, और चेतावनी दी कि बच्चे, बुजुर्ग

तथा शारीरिक रुप से अन्य संवेदनशील लोग लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क

में रहने से अपने स्वास्थ्य पर गम्भीर असर का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण कोई विचारधारा का मुद्दा नहीं है और इसे दलगत आरोप-प्रत्यारोप में नहीं बदलना चाहिए।

उन्होंने चर्चा की रूपरेखा में पूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया और कहा “मेरा मानना है कि एक अच्छा तरीका यह होगा कि हम चर्चा को इस आधार पर न रखें कि आपने क्या नहीं किया या हमने क्या नहीं किया, बल्कि इस पर रखें कि भविष्य में भारत के लोगों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा, “इस सदन में हर कोई इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ मानहानि केस में 23 दिसम्बर को सुनवाई

सुलतानपुर, 12 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। यह सुनवाई राहुल गांधी के अधिवक्ता

- सुनवाई शुक्रवार को होनी थी पर राहुल गांधी के वकील ने गवाह से जिरह के लिए समय मांगा इस लिए कोर्ट ने 23 दिसम्बर की तारीख दी है।

काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा समय लेने के कारण स्थगित हुई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की है।

कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1976 में 40 साल तक लोकसभा सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया था

2026 में यह अवधि पूरी हो रही है तथा लगभग सभी जनसंख्या की डिजिटल काउंटिंग भी पूरी हो जाएगी तथा इसके बाद लोकसभा सीटों का “डीलिमिटेशन” भी होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। भारत पाँच दशकों पोलिटिकल रिप्रैजेंटेशन की सबसे बड़ी पुनर्संरचना (रीकैलिब्रेशन) की ओर बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा आने वाले दो वर्षों में डिजिटल जनगणना पूरी करने के फैसले ने देश में एक जोरदार बहस को दोबारा शुरू कर दिया है।

यह कदम लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लम्बे समय से लंबित परिसीमन (डीलिमिटेशन) के लिए मंच तैयार करता है, एक ऐसा कदम, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों और जनसंख्या के मामले में स्थिर दक्षिणी राज्यों के बीच शक्ति

संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा। लोकसभा सीटों का अंतिम बार पुनर्वितरण 1970 के दशक की शुरुआत में हुआ था। उसके बाद 1976 में लगाई गई संवैधानिक रोक, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान न हो, ने जनसंख्या के आधार पर किसी भी बदलाव को रोक दिया। यह रोक 2026 में समाप्त हो रही है, जिससे एक नया राजनीतिक दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है।

ऊँचे पदों पर मौजूद सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि जैसे ही नई जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध होंगे, “परिसीमन तुरंत शुरू हो जाएगा।” इसके प्रभाव बहुत स्पष्ट होंगे। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्य, जहाँ आबादी लगातार

- दक्षिण भारत के प्रदेश: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र व तेलंगाना, इस “डीलिमिटेशन” से काफी आशंकित हैं।
- उनका भय है कि अगर “डीलिमिटेशन” का आधार केवल जनसंख्या ही हुई तो दक्षिण भारत की लगभग चालीस सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में और उत्तर भारत के राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 60 सीटों की वृद्धि होगी।
- और इसके बाद, उत्तर भारत की विधानसभा में विधायकों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे राज्यसभा में भी उत्तर भारत के प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और इसके बाद केन्द्र से राज्यों को आवंटित राशि में भी उत्तर भारत का हिस्सा बढ़ जाएगा।
- जबकि, दक्षिण भारत का योगदान केन्द्रीय सरकार के आर्थिक कोष में उत्तर भारत से ज्यादा है।

बढ़ी है, लोकसभा में अपनी प्रतिनिधित्व संख्या में बड़ा फायदा उठाएंगे।

अनुमानों के मुताबिक, यदि पूरी तरह जनसंख्या अनुपात के आधार पर

परिसीमन किया गया, तो इन राज्यों को 40 से 60 नई लोकसभा सीटें मिल

सकती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 20 से 40 सीटें तक खो सकते हैं। महाराष्ट्र में भी सीटें घटने की संभावना है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी कम हुई है।

इस संभावित बदलाव से पूरे दक्षिण भारत में बेचैनी फैल गई है। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबु नायडू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिण भारत “राजनीतिक रूप (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल की बैठक में नहीं आए थरूर

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी की लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए। थरूर की प्रमुख बैठकों से बार-बार गैरहाजिरी को लेकर पार्टी के अंदर अब सवाल उठने लगे हैं। हालाँकि, शशि

- कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार तीसरी बार कांग्रेस सांसदों की बैठक से अनुपस्थित रहे हैं।

थरूर ने बैठक से अपनी अनुपस्थिति को लेकर पहले ही नेतृत्व को जानकारी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस के चीफ व्हिप का कहना है कि उन्हें उनकी अनुपस्थिति के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं, जिसको लेकर भी उन पर सवाल उठे हैं। अब वो कांग्रेस की औपचारिक बैठकों भी शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठने लाजिमी है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हर चीज़ की कीमत व्यक्ति की जेब और ज़रूरत के अनुसार होती है और शायद उसी के अनुसार वह अच्छी या बुरी होती है। –संतोष गोयल

राजस्थान में बढ़ता जा रहा है नशे का कारोबार

राजस्थान में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के खिलाफ पुलिस की छापेमारी और थरफकड़ के बावजूद नशाखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। नशे के खिलाफ एक बार फिर सरकारी मशीनरी ने कसर नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालौर और सांचौर सहित प्रदेशभर में पिछले कुछ वर्षों से एमडी, गांजा और स्मैक जैसे ड्रग्स का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस, एसओजी व एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में लगातार ऐसी फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, जहां रेगिस्तानी धोरों में बने अस्थायी शेल्टरों या खेत-खलिहानों के बीच बने स्थानों पर इस जानलेवा ड्रग का उत्पादन किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, अवैध प्रयोगशालाएं अक्सर दूर-दराज रेतिले क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जहां पड़च पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। पकड़ी गई फैक्ट्रियों में अधिकांश में रासायनिक उपकरण, ड्रग्स और तैयार एमडी पाउडर की बड़ी मात्रा मिली है जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जाता है। सांसद धनरथाम तिवाड़ी ने भी राज्यसभा में सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान में एक हजार किलोमीटर से लम्बी सीमा है और सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से जरिए नशीले पदार्थ गिराए जा रहे हैं। जिसे कई बार पकड़ा गया। यह एक रूठ बन गया है जिसके माध्यम से पाकिस्तान से होकर नशीले पदार्थ आते रहते हैं। इस कारण नशे की प्रवृत्ति और उसकी तस्करी पर कड़ी पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि बीएसएफ और सेना व स्थानीय पुलिस इस पर काम कर रही है। पर राजस्थान को सीमावर्ती क्षेत्रों में और अधिक पुलिस चौकियों के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। रात्रि को गश्त करने वाले उपकरण की भी आवश्यकता है।

पुलिस और अन्य एजेंसियों ने राजधानी जयपुर में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए शिक्षण संस्थानों के पास बड़ी कार्रवाई की है। शैक्षणिक संस्थानों के पास मादक पदार्थ बेचे जाने की खबरें आए दिन सामने आती रही है। इस दौरान दर्जनों ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें बहुत से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर सहित प्रदेशभर में पकड़ा धकड़ी जारी है। नशे के सौदागर बेखोफ होकर गली, मोहल्लों में अपना जाल फैलाकर युवाओं को मादक पदार्थों की लत लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नशे का सामान चाय पान की थडियों, मेडिकल स्टोर्स और शिक्षण संस्थाओं सहित राजधानी के विभिन्न स्थानों, कच्ची पक्की बस्तियों तथा चौक चौराहों के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पुडिया के नाम से स्मैक, एमडी, गांजा आदि अवैध नशे का कारोबार बिना रोकटोक चल रहा है। सुनसान रास्ते व खंडहर इमारतें नशा करने वाले बच्चों व युवाओं के विशेष अड्डे हैं। नशाखोरी की आदत नाबालिग बच्चों, किशोरों और युवाओं में अधिक देखने को मिल रही है। युवाओं के अलावा महिलाएँ भी इस धंधे में लिप्त हो रही हैं। इससे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर संकटों के बादल मंडराने लगे हैं। कभी चोरी-छिपे बिकने वाले नशे का सामान आज घड़ल्ले से बिक रहा है।

नशा, नशा का मूल है। यह स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिय्ठा को क्षय करता है। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूल जीवन को नष्ट कर देता है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे की लत से पीड़ित हैं। हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेक अपराधों के पीछे नशा एक बहुत बड़ी वजह है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करना, शादीशुदा व्यक्तियों द्वारा नशे में अपनी पत्नी से मारपीट करना आम बात है। मुँह, गले व फेफड़ों का कैंसर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, यकृत रोग, अवसाद एवं अन्य अनेक रोगों का मुख्य कारण विभिन्न प्रकार का नशा है ।

नशा नशा नशा आखिर ये नशा है क्या? व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदल देने

नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है की सरकार के साथ समाज जागरूक हो। यह अनेक सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक बुराइयों और बीमारियों की जड़ है। इससे दूर रहना समाज और देश के हित में है। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। हमारा समाज तभी स्वस्थ होगा जब हम इन बुराइयों से अपने को दूर कर लेंगे। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई और आपका नशा नहीं छुड़ा पाएगा। सबसे पहले मन में ठान लें कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं।

से हाथ धो बैठता है। यह केवल एक बीमारी नहीं है बल्कि यह अनेक रोगों की जननी भी है।

नशे के रूप में लोग शराब, गाँजा, जर्दा, ब्राउन.शुगर, कोकीन, स्मैक आदि मादक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के साथ सामाजिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ठीक नहीं हैं। नशे का आदी व्यक्ति समाज की दृष्टि से हेय हो जाता है, और उसकी सामाजिक क्रियाशीलता ज़ीरो हो जाती है, फिर भी वह व्यसन को नहीं छोड़ता है। धूपपान से फेफड़े में कैंसर होता है, वहाँ कोकीन, चरस, अफीम लोगों में उत्तेजना बढ़ाने का काम करती है, जिससे समाज में अपराध और गैरकानूनी हरकतों को बढ़ावा मिलता है। इन नशीली वस्तुओं के उपयोग से व्यक्ति पागल और सुप्तावस्था में चला जाता है। तम्बाकू के सेवन से तपेदिक, निमोनिया, साँस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके सेवन से जन और धन दोनों की हानि होती है।

आजादी के बाद देश में शराब की खपत 60 से 80 गुना अधिक बढ़ी है। यह भी सच है कि शराब की बिक्री से सरकार को एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है। मगर इस प्रकार की आय से हमारा सामाजिक ढांचा क्षत-विक्षत हो रहा है और परिवार के परिवार खत्म होते जा रहे हैं। हम विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में शराब बंदी के लिए कई बार आंदोलन हुआ, मगर सामाजिक, राजनीतिक चेतना के अभाव में इसे सफलता नहीं मिली। सरकार को राजस्व प्राप्ति का यह मोह त्यागना होगा तभी समाज और देश मजबूत होगा और हम इस आसुरी प्रवृत्ति के सेवन से दूर होंगे।

चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट अत्यधिक डरावनी है। इस फाउंडेशन का एक सर्वे बताता है कि देश में नशाखोरी करने वाले 65 प्रतिशत लोगों की उम्र 18 वर्ष से भी कम है। संस्था का यह भी कहना है कि इसमें युवाओं की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग नशे की चपेट में है। इनका अस्सर बच्चों पर भी पड़ रहा है। इन पर नशा न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक दुष्प्रभाव डाल रहा है। नशे की पूर्ति के लिए अपराध से भी वह हिचक नहीं रहे हैं। थिंक जैज नामक एक स्वतंत्र संस्था की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के बाद देश में नशीले पदार्थों की खपत तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है नशे की यह प्रवृत्ति देश की तरुणाई तक पहुँच गई है जिसके खतरनाक परिणामों से देश को जुझना पड़ेगा। नशे का कारोबार देश में 15 लाख करोड़ को पार कर चुका है। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आये दिन न सिर्फ लोग गांजा-चरस-अफीम-सुलेशन-ड्रग्स, कोरेक्स और नशीली इंजेक्शन के आदि हो रहे हैं बल्कि इनके सेवन से लोग मौत के शिकार भी हो रहे हैं। नशा करने से तिवर, किडनी और फेफड़े खराब हो जाते हैं। डिड्रेशन, मानसिक अस्थिरता, फोकस और कंसन्ट्रेशन लॉस, भ्रम की बीमारी, आत्महत्या करने का खतरा और इन जैसी कई बीमारियों के होने का खतरा होता है। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ रही है। कुछ में तो नशे की ज़रूरत भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की तरफ से कराए गए एक सर्वे में पता चला है कि मादक पदार्थों का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान की तरफ से आता है। पाकिस्तान की सीमा से सरे राजस्थान और पंजाब के साथ ही मुंबई उसका सबसे पहला लक्ष्य होता है। नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है की सरकार के साथ समाज जागरूक हो। यह अनेक सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक बुराइयों और बीमारियों की जड़ है। इससे दूर रहना समाज और देश के हित में है। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। हमारा समाज तभी स्वस्थ होगा जब हम इन बुराइयों से अपने को दूर कर लेंगे। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई और आपका नशा नहीं छुड़ा पाएगा। सबसे पहले मन में ठान लें कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं। फिर जो भी नशा कर रहे है उसकी तरफ देखे नहीं। अपने शरीर पर हो रहे शारीरिक नुक्सान का अनुमान करे। अपने परिवार और बच्चों के भविष्य को देखें। मन कड़ा करें और नशे को छोड़ दे।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार



प्रो. वीर बहादुर सिंह

यदि नहीं तो विगत कुछ वर्षों से सदर्नों में कुछ सदस्य विशेष रूप से विपक्षी अनर्गल बातें, शोरगुल और सामूहिक रुप से हुड़दंग कर विधाय कार्य होने में बाधा क्यों पैदा करते हैं? सभापति के लाख समझानें, विनयपूर्वक रोकने और सख्ती से कहने पर भी सदस्य चुप नहीं करते, आधे से अधिक समय सदन की कार्यवाही बाधित होना सामान्य सी बात हो गई है। अमूमन ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के सदस्य उत्पन्न करते हैं जो अत्यंत दुखद है क्योंकि कांग्रेस आजादी उपरांत अनेक वर्षों तक शासन में रही और सदन की परम्पराओं का पालन हुआ उसे तो फिर बड़े होने के नाते सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता।

सदैव सत्ता में बने रहने की ललक संभवतः उसे जनता के हितों

के मुद्दों पर भी सकारात्मकता के विपरीत रुख अपनाने को विवश होना पड़ता है। इंदिरा गाँधी ने भी यही किया था। न्यायालय की रूलिंग नहीं मानी क्योंकि उनकी सोच भी सत्ता में सदैव बने रहने की ही थी। उनकी उस ललक की परणिति आपातकाल में बदल गई और फिर नतीजा देश दुनियाँ ने देखा। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि श्रीमती गाँधी जैसा कठोर व्यक्तित्व आज किसी कांग्रेस नेता में नहीं, भले ही पार्टी डोल पीटती रहे।

लोगों से निपटने के लिए सभापति के पास शक्तियाँ होती हैं कि ऐसे ढीठ सदस्यों को मार्शल बुला कर सदन के बाहर का रास्ता दिखा दे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अथवा पूरे टर्म के लिए लेकिन यह देखा गया है कि सभापति शायद ही ऐसा कठोर निर्णय लेते हों, और इसी ढीलपोल का नतीजा है कि कतिपय सदस्य अनुशासनहीनता पर उतर सदन की कार्यवाही बाधित करने से नहीं चूकते।

मालूम नहीं एजेंडा के अनुसार विधायी कार्य सरकार कैसे पूरा करवाती है? मैं सभापति की शक्तिओं के उपयोग पर यहाँ कुछ अधिक नहीं लिखना चाहता लेकिन उदाहरण के लिए यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के भाषण के बीच बाधा उत्पन्न करे तो उसे एक पूर्व निर्धारित समय के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखाया जाय।

व्यवस्था कायम रखने वास्ते यह

कठोरात ज़रूरी है। दूसरा यह भी निश्चित है कि जिन लोगों को जनता चुनकर लोकसभा और विधान सभा भेजती है वे निश्चित रूप से ऐसी हरकत से संविधान का मखौल उड़ाते ही प्रतीत होते हैं और कार्यवाही देखने वाली देश विदेश की जनता के समक्ष एक मटमैली तस्वीर ही पेश करते हैं।

देश के आम नागरिक और पेशे से शिक्षक होने के नाते मुझे सदन के ऐसे माहौल से पीड़ा होती है। निराकरण और स्थिति में बेहतर बदलाव वास्ते मेरी अनुसंशा है ऐसा करते समय मैं इस बात से सजग हूँ कि सदन के प्रत्येक सत्र की एक विस्तृत सारिणी बने यदि पहले से नहीं बनी है तो, जिसमे प्रतिदिन सदन के सुचारु चलने का अंकन हो और कितने समय सदन की कार्यवाही बाधित रही और किसके द्वारा, इनका विवरण देश को प्रतिदिन बताया जाय।

यह सुझाव देते समय मेरा सदन की नियामवली पर कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। सदन की पूरी कार्यवाही प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन पर जनता को पढ़ने और देखने को मिले । जिससे जनता आंकलन कर सके कि उनके प्रतिनिधि का सदन में कैसा व्यवहार और योगदान रहा? जो सदस्य विधाय कार्य में रूकावट डालते हैं क्या ऐसा करना संविधान सम्मत है ? यदि नहीं तो उसकारिाकोई रखकर उनके विरुद्ध कार्यवाही हो और पूरा देश देखे। इन

कृत्यों को जनता से छिपाकर रखना और फिर धुला देना अथवा नजरअंदाज कर देना बुद्धिमानी नहीं अपितु जनता के प्रति अविश्वसास है।

किसी ने चुनाव जीतकर यदि लोकसभा या विधान सभा की सदस्यता हासिल कर ली है तो उसे उद्घाता, अनुशासनहीनता, अभद्रता और विधायी कार्य में रूकावट डालने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। ऐसे कारकों से निपटने की प्रधान मंत्री, सभापति और कुछ अन्य की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की गरिमा और वातावरण को अनुकूल बनाये रखने में उन्हें अपने पद के अनुसार निर्लिप्त रहने की नहीं बल्कि सजग प्रहरी और सहयोगी सदस्य होने का भी जिम्मेदारी है। एक अनुशासनहीन सदस्य के प्रति नरमी बरतना ठीक नहीं केवल इसलिए कि वो सदन का निर्वाचित सदस्य है।

मेरा मानना है कि सदन की कार्यवाही के लिए कोई प्रक्रिया और उसके नियम यदि निर्धारित नहीं है तो किये जायें। सदस्य किसी के भाषण के बीच वाधा उत्पन्न नहीं कर सकते ऐसा करना निर्लज्जता और मूर्खता है? इसलिए मेरा सुझाव है कि दो तीन वरिष्ठ लोगों की एक समिति गठित कर पूरी नियमावली की रचना कर ली जाय और यदि पूर्व की नियमावली मौजूद है तो उसका पुनरीक्षण कर लिया जाय। किसी की भी बोलने के बारे में विस्तृत नियम होना आवश्यक है। इन नियमों

की प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जाय और इनका पालन करने के लिए उससे शपथ भरवाई जाय। अन्यथा आचरण पर नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हो जिनमें सदन से निष्कासन और आर्थिक शांति शामिल हो। यदि देश को यह बताना है कि उसकी डेमोक्रेसी अब काफी परिपक्व हो चुकी है दो वैसा आचरण सदन में दिखना चाहिए।

टेलीविज़न के होते हुए अब विदेशों के लोग भी सदन की कार्यवाही देखते हैं। सदन में विरोध स्वरूप अनावश्यक शोरगुल, अव्यवस्था और हुड़दंग विधायी कार्यवाही में रूकावट तो डालते ही है एक सभ्रांत समाज की छवि को धूमिल भी करते हैं।

मैं पाठकों से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर यदि वे भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो उसे अपने वाणी अथवा लेखनी से उजागर करें और अपना सकारात्मक योगदान देकर देश का मान बढ़ाएं। चुनाव से लेकर और निर्वाचन तक जनप्रतिनिधि की भूमिका की निरंतर पड़ताल विद्वतजन और पत्रकार लोग करते रहें और उसे अखबार में प्रकाशित भी करते रहें यह सर्वदा उचित ही होगा। इस विषय पर अभी इतना ही। पाठक समुचित प्रतिक्रिया अवश्य दें ऐसी आशा।

—प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता
डैरी व् खाड़ प्रौद्योगिकी,
महाराष्ट्र प्रताप कृषि एवं
प्रौद्योगिकी वि.वि., उदयपुर।

आयोग ने विचारित सूचियां जारी की

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा- 2024 अंतर्गत डाइंग, म्यूजिक एवं राजस्थानी विषय के पदों के लिए विचारित सूचियां जारी की गई है। इन सूचियों में डाइंग के 8, म्यूजिक के 1 एवं राजस्थानी विषय के पदों के लिए 8 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

अलवर स्थित ‘‘सिलीसेढ़ झील’’ रामसर साइट के रूप में घोषित

अलवर, (निसं)। अलवर में स्थित सिलीसेढ़ झील को आद्रभूमि पर कन्वेंशन ने रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के विलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह जैव-विविधता, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है।

आकर्षक सारसों से लेकर रंग-बिरंगे किंगफिशर्स तक-यह झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, जहाँ आकाश पंखों की अद्भुत दुनिया से जीवंत हो उठता है। 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखने का अवसर और सरिस्का टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार होने के कारण यह झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है।

इस उपलब्धि पर अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं अलवर के लोगों, विशेषकर सिलीसेढ़ झील के आसपास रहने वाले सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि अलवर की इस झील को वैश्विक पहचान मिली है। यह हमारी साझा उपलब्धि है। हम इस रामसर साइट के सम्मान के साथ सिलीसेढ़ झील के आसपास पर्यटन, जैव विविधता और जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन, साथ ही जलवायु सुरक्षा और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के काम को और मजबूती दे पायेंगे।

गौरतलब है कि 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित यह ऐतिहासिक झील अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिसका प्रमाण झील के चारों ओर बने जल-वाहिकाओं (एक्वाडक्ट्स) में मिलता है।



अलवर में स्थित सिलीसेढ़ झील।

भीलवाड़ा के राजोला गांव में विद्यालय भवन लंबे समय से जर्जर, विद्यार्थी परेशान

स्कूल भवन के जर्जर होने और वैकल्पिक व्यवस्था खत्म होने के बाद अब ग्रामीण प्रदर्शन कर स्कूल पर तालेबंदी करने को मजबूर

भीलवाड़ा, (निसं)। जहां एक ओर सरकारें शिक्षा का अधिकार और स्कूल चलेँ हम जैसे नारों से शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा करती है, वहीं पंचायत समिति सुवाणा की ग्राम पंचायत देवली के राजोला गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (आठवीं तक संचालित) के लगभग 90 विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। स्कूल भवन के जर्जर होने और वैकल्पिक व्यवस्था खत्म होने के बाद अब ग्रामीण प्रदर्शन कर स्कूल पर तालेबंदी करने को मजबूर हो गए हैं।

जनकारी के अनुसार राजोला का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय पहले इस जर्जर भवन को बंद करवा दिया था। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय को करीब चार महीने से एक निजी जगह पर संचालित किया जा रहा था। यह अस्थाई व्यवस्था बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने का एकमात्र सहारा थी। दुर्भाग्यवश, जिस निजी भवन में स्कूल चल रहा था, उसके मालिक ने अब अपनी जरूरत बताते हुए जगह देने से



विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने नया और सुरक्षित स्कूल भवन बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

मना कर दिया है। इसके चलते स्कूल के सामने संचालन का कोई विकल्प नहीं बचा है। श्रुक्वार को मजबूरी में ग्रामीणों ने स्कूल की तालेबंदी कर दी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की एकमात्र मांग है कि जर्जर हो चुके भवन

को तुरंत जमींदोज कर उसकी जगह नया और सुरक्षित भवन बनाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई बिना किसी बाधा के शुरू हो सके।

बच्चों का भविष्य खतरे में : -

राजोला विद्यालय में पढ़ने वाले ये 90

विद्यार्थी गांव के भविष्य की नींव हैं। स्कूल पर ताला लगने का सीधा अर्थ है, इन बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनना। शिक्षा के अभाव में उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि

■ **राजोला का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से जर्जर भवन में संचालित हो रहा था**

■ **छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने कुछ समय पहले इस जर्जर भवन को बंद करवा दिया था**

हम चार महीने तक जैसे-तैसे बच्चों को निजी जगह पर पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वह भी बंद हो गया। सरकार एक तरफ कहती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित छत तक नहीं मिल पा रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन निर्माण शुरू करें, या कम से कम तब तक के लिए कोई अस्थाई और सुरक्षित वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं।



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

शनिवार 13 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रविवार प्रातः 8:18 तक, आयुष्मान योग दिन 11:16 तक, गर करण सायं 4:38 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:28 से 9:46 तक, चर 12:21 से 1:38 तक, लाभ-अमृत 1:38 से 4:13 तक।

राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:11, सूर्यास्त 5:31 तक



मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



वृष

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी और आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।



वृश्चिक

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।



मिथुन

घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।



कर्क

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

नवीन कार्यों के संबंध में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त हो सकता है और धन का अपव्यय हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।



कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान हो सकता है। आज बर्ते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।



कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।



मीन

परिवार में धार्मिक-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

नवाचार ही अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास के इंजन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपये की फंडिंग बांटी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार की शुरूआत जिज्ञासा से ही होती है और तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आगे बढ़ने से ही देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह सुखद है कि आज राजस्थान के युवा तकनीक में नाम कमा रहे हैं। शर्मा शुक्रवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 'नवाचार दिवस-स्टार्टअप कॉन्क्लेव' समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों और हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने कहा कि आईस्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। ये स्टार्टअप न केवल उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। शर्मा ने कहा कि स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं बड़ चढ़कर आगे आ रही हैं। आईस्टार्ट पर पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप में से 2 हजार 600 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं तथा 288 स्टार्टअप का नेतृत्व हमारे युवा विद्यार्थी कर रहे हैं। आईस्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1 लाख 16 हजार से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सफल स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी संभावनाओं वाले



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ‘नवाचार दिवस-स्टार्टअप कॉन्क्लेव’ समारोह में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने में मददगार साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 2025-26 के बजट में राजस्थान डिजिफेस्ट के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा टाई ग्लोबल समिट के सहयोग से जनवरी 2026 में जयपुर में इस डिजिफेस्ट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इनोवेशन डे से आगामी राजस्थान डिजिफेस्ट 2026 के लिए एक सशक्त मंच तैयार हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान डिजिफेस्ट भारत के सबसे बड़े नवाचार सम्मेलनों में से एक होगा। इसमें 10 हजार से अधिक प्रतिभागी, 500 से अधिक निवेशक, 300 प्रदर्शक, 200 वक्ता, 100 सत्र और 100 स्टार्टअप पिच शामिल होंगे। शर्मा ने कहा कि हमने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, इनरव्यूेशन सेंटर्स

स्थापित करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई तकनीक में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर स्थापित कर रहे हैं। एबीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के तहत हममें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस (लीप) प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीन सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने पर काम कर रहे हैं। राजस्थान राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसी हमारी पहलों से निवेशकों का

भरोसा काफी मजबूत हुआ है। गत वर्ष आयोजित इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हुए और उनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर आने लगे हैं। इस समिट से एक तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में राजस्थान की स्थिति और मजबूत हुई है। हमने पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है और इसी दिशा में हमने अब तक 92 हजार युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की हैं तथा इसी माह में ही लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही, निजी क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने ढाई लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। युवाओं के विकास के लिए नवीन युवा पॉलिसी भी लागे जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नवाचारों की खान है। वर्ष 2030 तक हम प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की

इकॉनोमी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडारण, वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। हमने दो दर्जन से अधिक नई नीतियां बनाई हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना आसान हुआ है। इस दौरान सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड़ ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश की सोच भी बदली है। इनोवेशन ही विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन है और इस इंजन का टर्बोचार्जर राजस्थान में होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज संपर्क 2.0 और ई-मित्र हर गांव को सरकार से जोड़ रहे हैं। हमारी सरकार पहली बार डेटा सेंटर की पॉलिसी लेकर आई है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपये की फंडिंग का चेक सौंपा। कार्यक्रम में राजस्थान डिजिफेस्ट के टीजर एवं डिजिफेस्ट हेाथॉयन कारिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान थिलोफिलिया की कॉ-फाउंडर एवं सईओ श्रीमती चित्रा गुरनानी डागा तथा रीटाप के फाउंडर एवं सईओ श्री तुषार सुहालका ने अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आभार जताया। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता, डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल के संस्थापक अजय डाटा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में युवा उद्यमी उपस्थित रहे।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से शुक्रवार को लोकभवन जयपुर में एयर मार्शल, कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड नागेश कपूर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीमा क्षेत्रों के विकास और सैनिक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर राज्यपाल से संवाद किया।

जे.डी.ए. ने नवीन अवैध कॉलोनी पूर्णतः ध्वस्त की

उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने निरीक्षण किया

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जून-12 में कालवाड़ रोड, जौबनेर रोड, मण्डा भोपावास, टोंक रोड, गोपालपुर बाईपास, जिला जयपुर शहर में ओचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी द्वारा कालवाड़ रोड, जौबनेर रोड, मण्डा भोपावास, टोंक रोड, गोपालपुर बाईपास, जिला जयपुर शहर में ओचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, उपनियंत्रक प्रवर्तन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा प्रवर्तन अधिकारी जौन-12, 02, 09, 13 भी उपस्थित रहे। निरीक्षण करने पर ठाम सरनाइंग, जिला जयपुर में मंदिर माफी की करीब 16 बीघा भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाई जाने पर उप

महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज प्रवर्तन दस्ते द्वारा जैसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भिक स्तर पर ही ध्वस्त किया गया। ग्राम कालवाड़ रोड जिला जयपुर में जौबनेर रोड कालवाड़ बस स्टैंड पर करीब 11 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाये भूमि को समतल कर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्वं में दो बार ध्वस्त किया गया था। उक्त कृषि भूमि पर पुनः बनाई गई मिट्टी-टोवल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाई जाने पर उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जौन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते जैसीबी मशीन की सहायता से प्रारिम्भिक स्तर पर ही पुनः ध्वस्त किया गया। ग्राम मण्डा, भोपावास, कालवाड़ रोड जिला जयपुर में करीब 40 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना

स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ मिट्टी डाली जा रही थी, जिसे मौके पर ही उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जौन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा प्रारिम्भिक स्तर पर ही रुकवाया गया। नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जौन-12, 02, 11, 09, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जापे, लेबर गाई एवं जौन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। प्रवर्तन प्रकोष्ठ जॉबिा द्वारा वर्ष 2025 में 370 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनियों बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।

भारत मंडपम में दो दिवसीय इंटरनेशनल जनमंगल सम्मेलन



नई दिल्ली के भारत मंडपम में दो दिवसीय इंटरनेशनल जनमंगल सम्मेलन में योग और उपवास के दो प्रसिद्ध संतों योग ऋषि स्वामी रामदेव और जैन संत अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आशीर्वाद प्राप्त किया।

नई दिल्ली। भारत मंडपम में दो दिवसीय "इंटरनेशनल जनमंगल सम्मेलन" आयोजित किया गया जिसमें योग और उपवास के दो प्रसिद्ध संतों योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज और जैन संत अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में, एक जन आंदोलन "हर मास - एक उपवास" (हर महीने 7 तारीख को एक बार उपवास) शुरू किया गया। यह द्वि-दिवसीय सम्मेलन 4 सत्रों में "जनमंगल की सम्यग्दृष्टि-उपवास, ध्यान, योग व स्वदेशी चिंतन" पर केंद्रित है। दोनों युग-पुरुषों ने जनमंगल के लिए "हर मास एक उपवास" महाभियान से मानवता को समस्त सिद्धिदायक महामंत्र देने का संकल्प किया है। इस आंदोलन से देश के प्रमुख संतगण, राजनेता तथा विख्यात हस्तियों के साथ-साथ दुनिया भर में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। सम्मेलन का अध्यक्षीय उद्घोषण देते हुए लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने कहा भारत मण्डपम की यह भूमि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विज्ञान का अद्भुत साक्षी बन रहा है। पूज्य अंतर्मना ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, विज्ञान, वैयक्तिक विकास व आत्म विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनका तप-तपस्या अद्भुत है। यह आयोजन अध्यात्म और कर्मयोग का दिव्य संगम है जो निश्चित ही देश व दुनिया को नया

संदेश देगा। देश की राजधानी दिल्ली से देश को संदेश जाएगा और देश से दुनिया तक यह बात पहुंचेगी। जहां एक ओर आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान का दर्शन देकर आत्म विकास का मार्ग बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर स्वामी रामदेव जी महाराज कर्मयोग, भारतीय शिक्षा, स्वदेशी जीवन और योग विज्ञान के माध्यम से देश व दुनिया को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने एक माह-एक उपवास का संकल्प लेते हुए कहा कि भी माह में एक बार उपवास करूंगा। कार्यक्रम में अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज ने कहा कि उपवास आत्मिक ऊर्जा को जगाने वाला दिव्य साधन है। उपवास का उद्देश्य तन, मन व आत्मा को शुद्ध करना है। उपवास तन की स्वच्छता, मन के परिशोधन, जीवन के पुनर्गठन व जीवन के उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। उपवास के दौरान भावनाएँ नियंत्रित होती हैं, क्रोध घटता है, मन शांत होता है और ध्यान गहरा होता है। व्यक्ति नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर सकारात्मकता और मानसिक स्थिरता का अनुभव करता है। अंतर्मना ने कहा कि उपवास आत्मा का भोजन है जो साधक को आसक्ति से मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि उपवास का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह मन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। सम्मेलन में स्वामी रामदेव ने कहा

कि हर मत, पंथ, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान और शुभ प्रसंग में उपवास का समान रूप से प्रावधान और महत्व है। उपवास से शरीर, मन और अंतःकरण की शुद्धि होती है जिससे मनुष्य जोते जी जीवन से मुक्त हो जाता है। उपवास से मनुष्य सहज योग व सहज समाधि को उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने बताया कि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिवस तक निरंतर तथा अपने जीवनकाल में अभी तक 18 वर्ष उपवास करके (और अब तक 3500 से ज्यादा उपवास सिद्ध कर के) "उपवास शिरोमणी" की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जैन मुनि पीयूष सागर जी महाराज ने उपवास स्वस्थ जीवन का आधार है। उपवास करने से प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ जाती है। आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सोभाग्य है कि आज दिव्य संतगणों के मध्य उपस्थित रहने का अवसर मिला। उन्होंने स्वयं उपवास करते हुए 10-10 लोगों को उपवास के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वामी रामदेव जी महाराज से हमने ही नहीं पूरे विश्व ने योग, प्राणायाम, आयुर्वेद के ज्ञान सीखा है। सुप्रसिद्ध लिबर विशेषज्ञ डॉ. एस. के. सेरीन ने उपवास के वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा।

जयपुर पुलिस का ऑपरेशन वज्र : 26.50 लाख रुपये के 123 मोबाइल ट्रेस किए

जयपुर। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस की कारवाई लगातार तेज बनी हुई है। जहां साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में नवंबर माह में उल्लेखनीय सफलता मिली। जिले में विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन ठगी के मामलों में 123 मोबाइल फोन ट्रेस कर रिकवर किए गए। जिनकी कीमत करीब 26.50 लाख रुपये आंकी गई है। इसी अवधि में साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों के खातों में 27.15 लाख रुपये वापस जमा कराए गए, जबकि साइबर अपराधियों के खातों में फंसे 1.49 करोड़ रुपये होल्ड करवाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस थाना विश्वकर्मा व बनीपार्क थाने में दो मुकदमे दर्ज कर पांच आरोपियों सहित छह को 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया एसपी साइबर

■ साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान

सेल व तकनीकी टीम लगातार मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग पर काम कर रही है। इसके चलते विश्वकर्मा थाना इलाके में पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपित रवि शंकर और विनोद मीणा द्वारा ढाई हजार रुपये की दुकान किराए पर लेकर इन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जहां पर पुलिस को तलाशी के दौरान दोलतमंद बनने की किताब मिली। जब आरोपित रवि से इस बारे में पूछताछ की गई तो सामने आया कि उसे जल्दी से पैसे वाला बनना था। जिसके लिए उसने उसके खाते और अन्य लोगों के खातों में साइबर अपराध का पैसा मंगवाता था और उन पैसे को स्ट्रेबाजी एप में लगा देता था। दोनों के खिलाफ साइबर फ्रॉड से जुड़े साक्ष्य मिले हैं।

हाईकोर्ट बार के सोगरवाल अध्यक्ष, दीपेश महासचिव निर्वाचित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में राजीव सोगरवाल अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य को 532 मतों से हराया। सोगरवाल ने 1741 मत हासिल किए, जबकि शांडिल्य को 1209 मतों से संतोष कराना पड़ा। वहीं महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड 2748 मतों से जीत दर्ज की। इसी तरह उपाध्यक्ष के दो पदों पर अनुराग कलावटिया और सुनील शर्मा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर प्रीति शर्मा, पुस्तकालय सचिव के पद पर बाँबी दाता, संयुक्त सचिव पद पर हिमांशी मीणा, संयुक्त पुस्तकालय सचिव के पद पर प्रज्ञा पांडे और सांस्कृतिक सचिव पद पर उपासना आर्य विजयी हुई। इसके अलावा कार्यकारिणी के आठ पदों पर कुलदीप शर्मा, शुभम जैन, अनुश्री अठवाल, सौरभ तिवारी, अजय सिंह राजावत, नरेन्द्र पारीक, दुष्यंत सिंह नरूका और देवेन्द्र शर्मा निर्वाचित हुए। दूसरी तरफ दी बार एसोसिएशन, जयपुर के वार्षिक चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। कुल 4566



राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम में राजीव सोगरवाल अध्यक्ष तथा दीपेश शर्मा महासचिव बने।

मतदाताओं में से 4119 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में अध्यक्ष पद पर 7, उपाध्यक्ष के दो पदों पर 5, महासचिव पद पर 8 और संयुक्त सचिव पद पर 6 प्रत्याशी

चुनाव मैदान में हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए करीब 250 वकीलों की टीम बनाई गई थी और सीसीटीवी की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। मतों की गणना शनिवार को की जाएगी।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने 2024 बैच के प्रोबेशनर आईएएस से प्रेरक संवाद किया

सुशासन, संवेदना और तकनीक आधारित प्रशासन पर दिया जोर

जयपुर। पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने 2024 बैच के प्रोबेशनर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्हें आधुनिक, उत्तरदायी और जन केंद्रित प्रशासन का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर तेजी से बदल रहा है-चुनौतियाँ भी नई हैं और समाधान भी। सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक-इन्हीं तीन स्तंभों पर भविष्य का प्रशासन खड़ा है। डीजीपी शर्मा ने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रशासनिक समन्वय, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, सामाजिक संवेदनशीलता तथा जनता से संवाद की रणनीतियाँ साझा कीं। उन्होंने सोशल मीडिया के निमंत्रण उपयोग, नेतृत्व क्षमता और नैतिक आचरण को प्रभावी प्रशासन की अनिवार्य शर्त बताया। डीजीपी शर्मा ने कहा कि आप शासन व्यवस्था की वह नई पीढ़ी है, जो विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन को नई दिशा देगा। हर निर्णय में ईमानदारी, संवेदना और जनहित को सर्वोपरि रखें।

वरिष्ठ अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन

इस मौके पर डीआईजी सीबी दीपक भार्गव ने राजस्थान पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रशासनिक सहयोग की



पुलिस मुख्यालय जयपुर में डी.जी.पी. राजीव कुमार शर्मा ने 2024 बैच के प्रोबेशनर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्हें आधुनिक, उत्तरदायी और जन केंद्रित प्रशासन का मूल मंत्र दिया।

प्रक्रियाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।आईजी एसएसबी अंशुमान भोमिया ने डीएम-एसपी समन्वय की महत्ता, कानून-व्यवस्था प्रबंधन में परस्पर सहयोग की भूमिका और जिला प्रशासन-पुलिस प्रशासन के बीच निर्बाध प्रणाली के उदाहरण साझा किए। वहीं आईजी कानून-व्यवस्था अनिल टांक ने राजस्थान की विशिष्ट परिस्थितियों, भौगोलिक चुनौतियों, जनजातीय क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में प्रशासनिक दृष्टिकोण पर विचार रखे।

संवाद के दौरान प्रोबेशनर आईएसएस अधिकारियों ने भी अपने प्रश्न रखे, जिनका वरिष्ठ अधिकारियों ने समाधानात्मक उत्तर दिया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अकादमी में प्रशिक्षण लिया इससे पहले आईएसएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत आरपीए जयपुर में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जहां उन्हें प्रिवेंटिव एक्शन, निरोधात्मक कार्यवाही,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, हथियार एवं विस्फोटक संबंधी कानून, कारागार एवं बंदी प्रबंधन, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम तथा पुलिस अभियोजन एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की समझा जानकारी दी गई। इस सत्र ने न केवल उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण को मजबूत किया, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था की जटिलताओं और पुलिसिंग संरचना की बारीकियों को समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

